निर्णय आरक्षित दिनांक : 18.04.2017

निर्णय इस पर दिया गयाः23.06.2017

<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>लिखित याचिका (पी. आई. एल.) सं.67/2011</u>

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के घायल/जेल गए आंदोलन की सेवा योजना, 2010 के समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों के मामले में।

..याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

उपस्थित:श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता (न्याय मित्र)

याचिकाकर्ता के लिए।

श्री एस. एन. बाबुलकर, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री परेश त्रिपाठी की सहायता से।

श्री रमन कुमार शाह, मध्यस्थ (व्यक्तिगत रूप से)

श्री एम. एस. पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आमिर मलिक, अधिवक्ता, श्री एस. के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. सिद्धार्थ जैन, अधिवक्ता, एम. सी. पंत, श्री महेश चंद्र पंत,

श्री सिद्धार्थ साह, श्री सी. के. शर्मा, हस्तक्षेप करने वालों के अधिवक्ता।

श्री रमन कुमार शाह, अधिवक्ता, मध्यस्थ (व्यक्तिगत रूप से)

कोरमः माननीय **<u>सुधांशु धूलिया, जे.</u>**

<u>माननीय यू. सी. ध्यानी, जे.</u>

<u>माननीय सुधांशु धूलिया, जे.</u>

1. उत्तराखंड का नया राज्य संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था,और इसकी स्थापना 9 नवंबर, 2000 को की गई थी, जिसे "नियुक्त दिवस" के रूप में जाना जाता है। कानूनी शुद्ध रूप से, नए राज्य का गठन एक विधायी अधिनियम था, जिसका स्रोत भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में है।फिर भी, कई लोगों के लिए जो इसके गठन के पिछले वर्षों के दौरान उथल-पुथल की घटनाओं के गवाह थे, उत्तराखंड का निर्माण भी, बड़े पैमाने पर, एक नए राज्य के लिए वर्षों की मांग और संघर्ष के लिए एक उपयुक्त चरमोत्कर्ष था।यह एक विचार की पराकाष्ठा थी-उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को भारत संघ में एक अलग और विशिष्ट इकाई बनाने का विचार!

2. नए राज्य उत्तराखंड के लिए इस आंदोलन की अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शनों, लंबे जुलूसों, धरना-प्रदर्शनों में हुई, जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों और महिलाओं को कारावास, कई स्थानों पर लाठीचार्ज, चोटों *और* यहां तक कि मौत भी हुई।अपने गठन के पश्चात नए राज्य ने "आंदोलनकारी" 2 के योगदान को स्वीकार किया और उन्हें कुछ लाभ प्रदान किए, जैसे कि मुफ्त बस पास, विधानसभा में आसान प्रवेश आदि। इसके अलावा, वर्ष 2004 में उत्तराखंड सरकार ने न मात्र "आंदोलनकरियों" को बिना किसी परीक्षा या प्रतिस्पर्धा के सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति दी, बल्कि उनके लिए सरकारी सेवा में भी आरक्षण दिया।इस पी. आई. एल. में हम इस अधिनियम की वैधता की जांच करें, जिसके द्वारा सरकारी सेवा में

1. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

2. यहाँ "अंदोलनकारी" शब्द का अर्थ होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1990 के दशक में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में एक अलग राज्य, जो उत्तराखंड राज्य है, के लिए आंदोलन में भाग लिया हो।

"अंदोलनकरियों" को एक बार की सीधी नियुक्ति के साथ-साथ आरक्षण दिया गया है।

3. 11.08.2004 पर दो सरकारी आदेश पारित किए गए थे।पहला आदेश जी. ओ. नं. 1269/2004 है।इस सरकारी आदेश में सरकारी सेवा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर "आंदोलनकारी" की नियुक्ति का प्रावधान है, जो पदों के लिए उनकी योग्यता के अधीन है।ये नियुक्तियाँ बिना किसी चयन प्रक्रिया के की जानी थीं।उत्तराखंड आंदोलन में "आंदोलनकारी" होना ही एकमात्र मानदंड था।उपरोक्त सरकारी आदेश में "आंदोलनकारी" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान या तो "घायल" हुआ था या सात दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहा था।

4. दूसरा सरकारी आदेश जो उसी तिथि का है अर्थात 11.08.2004 है जी. ओ. नंबर. 1270/2004।इस सरकारी आदेश में सभी सरकारी सेवाओं में, यानी प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के पदों में "आंदोलनकारी" के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।यहाँ एक "आंदोलनकारी" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सात दिनों से भी कम समय तक जेल में रहा था!

5. इस अदालत में दो याचिकाएं दायर की गईं।पहला 2007 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 945, करुणेश जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, और दूसरा 2009 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 301 है।

नारायण सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।इन दोनों याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने सरकारी आदेश संख्या 1269/2004 दिनांक 11.08.2004 में दी गई "आंदोलनकारी" की परिभाषा के से "आंदोलनकारी" होने का दावा किया।उनका मामला यह था कि हालांकि जी. ओ. के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी पहचान "अंडोलंकरी" के रूप में की गई थी, फिर भी उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई, जैसा कि उपरोक्त सरकारी आदेश के से प्रदान किया गया था।इसलिए उन्होंने राज्य के अधिकारियों को नियुक्ति देने का परमादेश देने के लिए एक परमादेश पत्र की मांग की, जो कि उनका अधिकार था, जी. ओ. दिनांक 11.08.2004, जी. ओ. संख्या 1269/2004 और 1270/2004 के आधार पर।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष ये मामले उठाए थे, का मत यह था की ऐसी नियुक्तियों का प्रावधान सरकारी सेवा में कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 में पहले से ही नियम मौजूद हैं। .इसके अग्रेतर चूंकि ये सरकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के से नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं और भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसलिए विद्वान

न्यायाधीश ने न मात्र याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, बल्कि इन याचिकाओं को खारिज करते हुए, उन्होंने अपने निर्णय और आदेश दिनांकित 11.05.2010 द्वारा 11.08.2004 के सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है।

7. इन याचिकाओं के खारिज होने के कुछ ही दिनों पश्चात उत्तराखंड सरकार ने 20.05.2010 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में अपने नियम बनाए। जिसे "उत्तराखंड राज्य आंदोलन के घायल/जेल गए आंदोलन की सेवा नियमावली, 2010" के रूप में जाना जाता है, "आंदोलनकारियों" को सरकारी सेवा में आरक्षण प्रदान करता है।इन नियमों में राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों पर सरकारी सेवा में सभी "आंदोलनकारियों" की एक बार नियुक्ति का प्रावधान है।याचिकाकर्ता करुणेश जोशी (2007 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 945 में याचिकाकर्ता) ने तुरंत इस आधार पर इस अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की कि चूंकि उनकी रिट याचिका को अस्वीकार करने का मुख्य आधार पहले यह था कि ऐसी नियुक्ति मात्र एक कार्यकारी आदेश के आधार पर नहीं की जा सकती है और चूंकि अब नियम बनाए गए हैं, इसलिए, दिनांक 11.05.2010 के निर्णय और आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने समीक्षा आवेदन में मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया, जिसे उनके द्वारा खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही विद्वान न्यायाधीश ने आदेश दिया कि मामले को एक जनहित याचिका के रूप में माना जाए, जो माननीय मुख्य

न्यायाधीश की मंजूरी के अधीन हो।आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने प्रथमदृष्टया पाया कि 20 मई, 2010 के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के से बनाए गए नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की जांच में खड़े नहीं हो सकते हैं।हालाँकि न्यायालय की मत है कि इस समीक्षा याचिका में इस प्रश्न पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, लेकिन साथ ही, न्यायालय मूक दर्शक नहीं हो सकता है यद्यपि सरकार को लोगों के एक निश्चित वर्ग को लाभ देने की अनुमति नहीं दे सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 यद्यपि 16 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है।
>
> ..
>
> i) नतीजतन, समीक्षा आवेदन को खारिज करते समय, न्यायालय पंजीकरण को निर्देश देता है कि वह न्यायालय के इस आदेश को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे, इस आदेश को पी. आई. एल. याचिका के रूप में या पी. आई. एल. पत्र के रूप में माने और इसके परिणामस्वरूप उनके लॉर्डशिप की प्रशासनिक मंजूरी, पंजीकरण को मामले को पी. आई. एल. के रूप में एक अलग मामले के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। मामले का शीर्षक "उत्तराखंड राज्य आंदोलन के खयाल/जेल गए आंदोलन की सेवा नियमावली, 2010 के से समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों के मामले में होगा।"

9. बाद में मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के साथ, मामले को एक जनहित याचिका के रूप में लिया गया और इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 26.08.2013 पर इस जनहित याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित किएः-

> "राज्य के वकील ने समय-समय पर आश्वासन दिया कि वह यह दिखाने के लिए अभिलेख सामग्री लाएंगे कि आंदोलनकारियों का *चयन* कैसे किया गया है। आज तक जो प्रस्तुत किए गए हैं और हमारे द्वारा देखे गए हैं, उनसे पता चलता है कि जो लोग शांतिपूर्ण *तरीके* से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भुला दिया गया है, लेकिन मात्र उपद्रवियों को ही लाभ दिया गया है।इसके

> अलावा, प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार राज्य की पसंद के लोगों को सार्वजनिक नियुक्तियां देकर और नागरिकों द्वारा प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें खुला रखने की अनुमति नहीं देकर जो कुछ भी किया है, वह करने की किसी भी शक्ति से वंचित है और तदनुसार, उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के उप-अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है।
>
> 2. तदनुसार, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं अग्रेतर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं; नीति/नियमों के आधार पर राज्य को कोई अग्रेतर नियुक्ति देने से रोकते हैं जो वर्तमान रिट याचिका का विषय है।"

10. हमें बार में बताया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मुद्दा वास्तव में सरकारी सेवा में "आंदोलनकरियों" के पक्ष में किए आरक्षण से संबंधित नहीं था, बल्कि यह सरकारी आदेश संख्या 1269/2004 द्वारा दी गई सीधी नियुक्तियों के बारे में था। दिनांकित 11.08.2004 और बाद के नियम।1270/2004 दिनांकित अन्य सरकारी आदेश, जो कि 11.08.2004 दिनांकित भी है, पर कभी भी औपचारिक रूप से सवाल नहीं उठाया गया है।फिर भी, तथ्य यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पी. आई. एल. के रूप में इस मामले के बाद के संज्ञान और उसमें 26.08.2013 पर पारित आदेश के पश्चात सरकारी आदेश संख्या 1270/2004 के कार्यान्वयन को भी रोक दिया गया है और "अंदोलनकरियों" से संबंधित आरक्षण भी अप्रभावी हैं।यह अभिलेख पर रखा जाना चाहिए कि हम इस जनहित याचिका में दोनों सरकारी आदेशों यानी 1269/2004 और 1270/2004 की वैधता के साथ-साथ इन दोनों आदेशों और नियमों को आगे बढ़ाने के लिए पारित किए गए आदेशों की जांच कर रहे हैं।दूसरे शब्दों में, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ये नियुक्तियां "आंदोलनकारी" होने के एकमात्र मानदंड पर की जा सकती हैं और क्या

कानून के से सार्वजनिक सेवा में "आंदोलनकारी" के लिए आरक्षण की अनुमति है।

11. हमें यह भी ध्यान दें चाहिए कि इस माननीय न्यायालय (दिनांक 1) के उपरोक्त आदेशों के परिणामस्वरूप, प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सरकारी सेवा में विभिन्न पदों के लिए पहले से ही शुरू की गई चयन प्रक्रिया रुक गई क्योंकि उन सभी में "आंदोलनकरियों" या उनके परिवार के सदस्यों के लिए 10 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान था।हमने अपने अंतरिम आदेशों के माध्यम द्वारा राज्य लोक द्वारावा आयोग और अन्य निकायों को सभी पदों पर चयनित उम्मीदवारों की सूची घोषित करने का निर्देश देकर छोटी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है, सिवाय " आंदोलनकरियों " के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित को छोड़कर, इस जनहित याचिका के भाग्य के आधार पर समान संख्या में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की दो अलग-अलग सूचियां रखी हैं। हमें यह भी ध्यान दें चाहिए कि उपरोक्त अंतरिम क्रम में "राउडी" शब्द

खण्ड पीठ दिनांक 26.08.2013 को बाद में हमारे द्वारा हटा दिया गया था और यह शब्द अब अभिलेख का हिस्सा नहीं है।

12. दो सरकारी आदेशों और नियमों के अलावा, हमें बाद के सरकारी आदेशों की भी जांच करने की आवश्यकता है जिनके द्वारा आरक्षण का लाभ "अंदोलनकरियों" के परिवार के सदस्यों को दिया गया है।"परिवार के सदस्य" को पत्नी/पति, बेटे और अविवाहित या विधवा बेटी के रूप में परिभाषित किया गया है।

13. यह भी अभिलेख में रखा जाना चाहिए कि राज्य

विधानमंडल द्वारा एक विधेयक भी पारित किया गया था, जिसे उत्तराखंड आंदोलन और उनके आश्रित विधेयक, 2015 के "चिह्नित आंदोलनकारी" के लिए सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड आरक्षण के रूप में जाना जाता हैः- इस विधेयक में न मात्र सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत पद "आंदोलनकरियों" के लिए, बल्कि उनके "आश्रितों" के लिए भी आरक्षित करने का प्रावधान है।यह विधेयक, हालांकि वर्ष 2016 में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन अब तक इसे राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।

<u>वर्तमान पी. आई. एल. की प्रमुखता</u>

14. श्री रमन शाह (जो "आंदोलनकरियों" की ओर से व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे हैं) के साथ-साथ राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है, जिसे मुख्य प्रश्नों से निपटने से पहले सुलझाया जाना चाहिए।आपत्ति एक जनहित याचिका के रूप में वर्तमान मामले की स्थिरता के बारे में है, क्योंकि प्रतिवादी के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष मामला मुख्य रूप से एक सेवा का मामला है, जिसे जनहित याचिका में नहीं देखा जा सकता है।

15. राज्य द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितता की ओर भी इशारा किया गया है।हमारे समक्ष यह कहा गया है कि किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के रूप में कोई याचिका दायर नहीं की गई थी और न ही न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक पत्र पर संज्ञान लिया गया था और ये मात्र दो तरीके हैं जिनके द्वारा एक जनहित याचिका शुरू की जा सकती है, इस मामले को एक जनहित याचिका के रूप में शुरू करना ही प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।श्री रमन

कुमार शाह प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि वर्तमान याचिका ने दो मान्यता प्राप्त मार्गों में से किसी को भी नहीं लिया है, इसलिए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है।

16. जनहित याचिका की स्थिरता पर अपनी आपत्ति को साबित आदेश के लिए, प्रतिवादी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया है।पहला है गिरजेश **श्रीवास्तव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2010) 10** एस. सी. सी. **707 में रिपोर्ट किए** गए और दूसरा है **भोलानाथ मुखर्जी और अन्य बनाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेन्टनेरी महाविद्यालय और अन्य** (2011) 5 **एस. सी. सी. 464** में रिपोर्ट किए गए।ये वे दो मामले हैं जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक जनहित याचिका में एक सेवा मामले को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है।

17. ऊपर उद्धृत दो मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को दोहराया गया है जो यह है कि जो मामले शुद्ध रूप से "सेवा" की प्रकृति के हैं, उन्हें जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दो मामलों में, मुख्य रूप से दो पक्षों या अलग-अलग व्यक्तियों के बीच एक सेवा मामले से संबंधित विवाद था, और इस तरह इसे कभी भी एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। यह एक स्वीकृत कानूनी स्थिति है कि पी. आई. एल. के रूप में उपचार सेवा मामले में उपलब्ध नहीं है।गिरजेश श्रीवास्तव (ऊपर) के मामले में तथ्य यह था कि कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए मध्य प्रदेश राज्य में कुछ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का चयन किया गया था।इस चयन को पी. आई.

एल. में चुनौती दी गई थी, जिसकी अनुमति दी गई थी और चयन को निरस्त किया गया था।उम्मीदवारों द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया।उनकी अपील को स्वीकार करते हुए, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पी. आई. एल. को किसी सेवा मामले में दायर नहीं किया जा सकता है।इसी तरह भोलानाथ मुखर्जी (उपरोक्त) का मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पी. आई. एल. के रूप में दायर एक मामले से उत्पन्न हुआ था, जिसमें प्राथमिक प्रश्न वरिष्ठता का था।

18. फिर भी, हमारे सामने मामले की प्रकृति को देखते हुए, विद्वान महाधिवक्ता के साथ-साथ श्री रमन कुमार शाह के वर्तमान मामले को एक सेवा मामले के रूप में लेने के इस मूल प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाना चाहिए।हमारे सामने मुद्दा यह नहीं है कि कोई व्यक्ति ए या बी सरकारी सेवा में नियुक्ति का हकदार है या नहीं।हमारे सामने मुख्य मुद्दा यह है कि क्या "आंदोलनकरियों" के लिए सार्वजनिक सेवा में आरक्षण वैध रूप से किया जा सकता है, या क्या वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे हैं।यह मामला आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के लोगों के लिए चिंता का विषय होगा।यह एक ऐसा मामला है जहां किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में पद और नियुक्तियां दी जानी हैं, जिनमें से कई पहले ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो चुके हैं, बिना किसी चयन प्रक्रिया का सामना किए।सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का अंततः भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह

है कि इस न्यायालय के समक्ष एक चिंता जताई गई है कि राज्य की ओर से इस कार्रवाई ने उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों की वैध आकांक्षाओं को वंचित कर दिया है जो सार्वजनिक रोजगार और पदों के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो सीमित हैं।हस्तक्षेप करने वालों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ठीक यही रुख अपनाया गया है, जिन्हें उनके वकीलों श्री महेश चंद्र पंत और श्री सिद्धार्थ साह, श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम द्वारा सुना जा रहा है। ऐसा प्रतीत *होता है* कि इस मामले में न्यायालय मित्र ने भी इसी तरह की चिंता जताई है।

19. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को जनहित याचिका के रूप में एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए उनकी मत थी कि सरकारी सेवा में "आंदोलनकारियों" के लिए आरक्षण एक ऐसा मामला है जिसकी भारत के संविधान के मापदंड के भीतर जांच की जानी चाहिए और यह केवल एक सेवा का मामला नहीं है।मैं सम्मानपूर्वक इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

20. इसके अलावा इस अदालत की एक खण्ड पीठ ने पहले ही इस रिट याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के समक्ष मामले के बहुत बड़े निहितार्थ हैं और इसे किसी सेवा मामले की संकीर्ण सीमाओं में नहीं देखा जा सकता है।किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच की जानी चाहिए और यह केवल एक सेवा का मामला नहीं है जैसा कि इसे बनाया जा रहा है।दूसरा, एक सेवा मामले के रूप में भी, यह कुछ निजी व्यक्तियों से संबंधित मामला नहीं

है, जो सीमित संख्या में पदों या नियुक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन यहां भी मुद्दा वह है जो बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित है।

21. अब प्रक्रियात्मक भाग पर आते हैं।समाज और विशेष रूप से वादियों के लिए इसके बड़े लाभ के बावजूद, समय बीतने के साथ, मुकदमेबाजी के इस रूप (यानी पी. आई. एल.) का भी दुरुपयोग होने लगा है, और इसलिए इसकी काफी आलोचना हुई है।जनहित आदेश की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए (2010) **3 एस. सी. सी. 402 में रिपोर्ट किए गए** उत्तरांचल राज्य **बनाम बलवंत सिंह चौफाल** और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य निर्देश दिए, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों को निर्देश शामिल थे।इनमें से कुछ निर्देश जो बताए जाने चाहिए ऊपर दिए गए निर्णय के पैरा 181 में निम्नलिखित बातें दी गई हैं:-

> "181. हमने वर्तमान मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।हमने कई निर्णयों में इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा घोषित कानून की भी जांच की है।जनहित आदेश की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है:-
>
> (1) न्यायालयों को वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और बाहरी विचारों के लिए दायर जनहित याचिका को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित करना चाहिए और उस पर अंकुश लगाना चाहिए।
>
> (2) प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम बनाए।नतीजतन, हम अनुरोध करते हैं कि जिन

> उच्च न्यायालयों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर नियम बनाने चाहिए।प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की एक प्रति इसके तुरंत बाद इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए।
>
> "।

22. उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियम बनाए गए थे, जिन्हें राजपत्र में 20.05.2010 और एक नए अध्याय पर अधिसूचित किया गया था अर्थात् अध्याय XXI-A को न्यायालय के नियमों में जोड़ा गया था जिसे "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से जनहित याचिका की प्रकृति में लेखन" के रूप में चिह्नित किया गया था।

23. उक्त नियमों में, अध्याय 21-ए के नियम 2 (ए) में "पी. आई. एल. याचिका" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

> "(क)" पी. आई. एल.-याचिका "से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से एक" जनभावनापूर्ण व्यक्ति "द्वारा जनहित में किसी कारण का समर्थन करने के लिए दायर की गई याचिका अभिप्रेत है।"

24. नियम 2 (बी) "पी. आई. एल.-पत्र" को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

> "(ख)" "पी. आई. एल.-लेटर" "से" "मुख्य न्यायाधीश" "या" "महापंजीयक" "को संबोधित एक" "पत्र" "अभिप्रेत है, जो जनहित के मुद्दों को उठाता है और" "उच्च न्यायालय" "के हाथों न्यायिक पक्ष पर विचार के योग्य है।"

25. नियम 2 (सी) 'पत्र' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

> "(ग)" "पत्र" "से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के" "मुख्य न्यायाधीश" "या" "महापंजीयक" "को संबोधित एक पत्र अभिप्रेत है, जो किसी मुद्दे की शिकायत करता है, जनहित में किसी कारण का समर्थन करता है और" "उच्च न्यायालय" "द्वारा न्यायिक पक्ष पर विचार करने की इच्छा रखता है।"

26. उक्त नियमों का नियम 3 "पी. आई. एल.-याचिका" और "पी. आई. एल.-पत्र" के विषय के बारे में है, जिसमें सार्वजनिक महत्व के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

27. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर संदर्भित विद्वान जा चुसे है, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांकित आदेश 02.08.2011 के अनुसार एक समीक्षा याचिका में समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए मामले को जनहित याचिसे के रूप में लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा था। न्यायालय के नियमों के प्रावधानों को नंगे पढ़ने से पता चलेगा कि हमारे सामने विषय न मात्र सार्वजनिक महत्व से है, बल्कि नियम मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र या "संचार" को भी जनहित याचिसे के रूप में स्वीसेर करने की शक्ति देते हैं, यदि यह उस विषय के अंतर्गत आता है जिस पर संज्ञान लिया जा सकता है।उपरोक्त प्रावधान जो एक

संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, उन्हें अब उन प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो पहले से ही न्यायालय के नियमों के से थे।

28. न्यायालय के नियमों के अध्याय 5 नियम 2 के तहत, एकल न्यायाधीश की क्षेत्राधिकार को सेिभाषित किया गया है, जिसमें यह भी प्रावधान है कि "एक न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो

मामला जिसकी सुनवाई अकेले बैठे न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है या उसमें उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न की सुनवाई किसी बड़ी पीठ के निर्णय के लिए की जा सकती है।पीठ ने कहा, "यह प्रावधान एकल न्यायाधीश को कानून के प्रश्न पर किसी मामले को बड़ी पीठ को भेजने की शक्ति देता है।

29. पी. आई. एल. पर अध्याय 21-ए के साथ पठित अध्याय 5 नियम 2 किसी भी प्रकार के संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, कि इस मामले में, जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा है, वह भी पूरी तरह से न्यायालय के नियमों के से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार था।संक्षेप में, न्यायालय के नियमों के से, एकल न्यायाधीश के पास किसी मामले को बड़ी पीठ को भेजने की शक्तियां होती हैं और मुख्य न्यायाधीश के पास "संचार" या पत्र को जनहित याचिका के रूप में मानने की शक्तियां होती हैं। इसलिए मैं यहां प्रक्रियात्मक पहलू में भी कोई विसंगति नहीं देखता।

<u>किसी कार्यकारी आदेश द्वारा सरकारी सेवा में संरक्षण किए जा सकते हैं!</u>

30. दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने है, वह यह है कि क्या सरकार लोक सेवा में पदों और नियुक्तियों पर आरक्षण दे सकती है, मात्र एक अधिनियम के माध्यम से या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के से नियमों के माध्यम से या यहां तक कि एक कार्यकारी आदेश द्वारा भी किया जा सकता है।हालांकि "अंदोलनकरियों" को दी गई एक बार की नियुक्ति के लिए बाद में नियम बनाए गए थे, जो शुरू में सरकारी आदेश संख्या 1269/2004 द्वारा किए गए थे, लेकिन जहां तक

"अंदोलनकरियों" को दिए गए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बात है, तो मात्र सरकारी आदेश संख्या 1270/2004 और उसके बाद के सरकारी आदेश दिनांक 08.11.2006 और सरकारी आदेश संख्या 13.12.2011 प्रतीत होते हैं, जिसके द्वारा क्षैतिज आरक्षण का लाभ "अंदोलनकरियों" के आश्रितों और परिवार के सदस्यों को दिया गया था। इस विधेयक को "द उत्तराखंड आंदोलन और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2015, जिसे वर्ष 2016 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता (न्याय मित्र) के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों *के विद्वान* अधिवक्ता श्री महेश चंद्र पंत का कहना है कि चूंकि लोक सेवा में आरक्षण केवल कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया है, बिना किसी अधिनियम या नियमों के, इन सरकारी आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता है।

31. जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है, यह अब एकीकृत नहीं *है क्योंकि* इसका उत्तर इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और **अन्य मामले में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया** है।(3) एस. **सी. सी.217. इंदिरा साहनी में** बहुमत की मत थी कि सेवा में आरक्षण एक कार्यकारी आदेश द्वारा भी किया जा सकता है।एकमात्र चेतावनी यह मात्र कि इस तरह का आरक्षण मौजूदा नियमों या अधिनियम के साथ टकराव में नहीं होना चाहिए।

32. न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी (कनिया, सी. जे., वेंकटचल्ला, जे., अहमदी, जे. और स्वयं की ओर से) द्वारा गठित बहुमत मत में, विद्वान न्यायाधीशों द्वारा तैयार किए दो प्रश्न इस

प्रकार थेः

1. (क) क्या अनुच्छेद 16 (4) द्वारा अनुध्यात 'प्रावधान' अनिवार्य रूप से राज्य की विधायी शाखा द्वारा किया जाना चाहिए।

(b) यदि खंड (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या ऐसा प्रावधान करने वाला कार्यकारी आदेश इसे अनुच्छेद 309 के प्रावधान के बनाए गए नियम में शामिल किए बिना लागू करने योग्य है।?"

33. एक कार्यकारी आदेश द्वारा दिए गए आरक्षण के विरुद्ध इंदिरा साहनी में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में 'प्रावधान' शब्द का तार्किक रूप से अर्थ राज्य के विधायी विंग द्वारा किया गया प्रावधान है न कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा।तर्क यह था कि अनुच्छेद 16 (4) के से बनाए गए प्रावधान अन्य नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं और इसलिए प्रावधान संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है।गंभीर आशंकाएं भी जताई गईं कि यदि ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां कार्यपालिका को दी जाती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप इसका दुरुपयोग हो सकता है।चुनावी प्रक्रिया के पतन के उदाहरण दिए गए, जिसकी अपनी राजनीतिक और चुनावी मजबूरियां हैं और इसलिए, कार्यकारी आदेश द्वारा आरक्षण न्यायसंगत और निष्पक्ष कारणों के बजाय सरासर राजनीतिक और चुनावी मजबूरियों से किया जा सकता है।यह भी तर्क दिया गया कि यदि ऐसा प्रावधान मात्र राज्य की विधायी शाखा या संसद द्वारा किया जाना है, तो यह संसद या राज्य विधानमंडल में (जैसा भी मामला हो) सभी प्रकार की मत अग्रेतर अभ्यावेदन सुनने के पश्चात ही

किया जाएगा अग्रेतर इस तरह की बहस अग्रेतर चर्चा के पश्चात ही एक संतुलित अग्रेतर निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा।

34. यद्यपि उपरोक्त तर्क को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।इस पहलू पर चार माननीय न्यायाधीशों में से अधिकांश की सटीक मत इस प्रकार थीः

> पीठ ने कहा, "हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि क्या आदर्श या वांछनीय है, बल्कि संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 16 (4) में 'प्रावधान' अभिव्यक्ति का उचित अर्थ क्या है।हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में 'प्रावधान' अभिव्यक्ति का उपयोग बिना किसी योजना के नहीं किया गया है।अनुच्छेद 12 में 'राज्य' की परिभाषा के अनुसार, इसमें न मात्र भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल शामिल हैं, बल्कि भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि इस तरह के आरक्षण का उपाय न मात्र केंद्र और राज्य सरकारों के से सेवाओं के मामले में बल्कि अनुच्छेद 12 में निर्दिष्ट स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों की सेवाओं में भी प्रदान किया जा सकता है।'स्थानीय प्राधिकरण' शब्द को सामान्य खंड अधिनियम की खंड 3 (31) में परिभाषित किया गया है। यह सभी नगर

पालिकाओं, पंचायतों और इसी तरह के अन्य निकायों को शामिल करता है।'अन्य अधिकारी' अभिव्यक्ति पर अदालत ने व्यापक ध्यान दिया है।इसमें राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सभी वैधानिक प्राधिकरण और अन्य अभिकरण और उपकरण शामिल हैं।अब, क्या यह कहना उचित, संभव या व्यावहारिक होगा कि संसद या राज्य के विधानमंडल को इसके अलावा ऐसे सभी निकायों की सेवाओं में पदों/नियुक्तियों के आरक्षण और इसके अतिरिक्त केंद्र/राज्य सरकार के से सेवाओं के संबंध में प्रावधान करना चाहिए?

35. विद्वान न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 13 (3) (ए) में "कानून" की व्यापक परिभाषा पर भी जोर दिया, जिसका अर्थ न मात्र राज्य विधानमंडल द्वारा कानून होगा, बल्कि एक अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग भी होगा।यह इस कारण से और बहुत विचार के पश्चात था कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में उपयोग किया गया शब्द 'प्रावधान' है न कि 'कानून' जैसा कि अनुच्छेद 16 के खंड (3) और (5) और अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 में उपयोग किया गया है।

36. उपरोक्त तर्क देते समय, बहुमत की मत **एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649 के मामले पर भी** निर्भर थी, जिसका बाद में भारत के नियंत्रक **और महालेखा परीक्षक बनाम मोहन लाल मेहरोत्रा, (1992) 1 एस. सी. सी. 20** के मामले में

अनुसरण किया गया।इस आशंका के संबंध में कि कार्यपालिका द्वारा ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में आगाह कियाः

> "पिछड़ेपन का कोई भी निर्धारण एक व्यक्तिपरक अभ्यास नहीं है और न ही व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय है।जैसा कि उसमें कहा गया है-और पहले के निर्णयों द्वारा भी-अभ्यास एक वस्तुनिष्ठ है।नागरिकों के किसी भी वर्ग के समूह को पिछड़े के रूप में माने जाने से पहले कुछ वस्तुनिष्ठ सामाजिक और अन्य मानदंडों को पूरा करना होगा।यदि कार्यपालिका संपार्श्विक कारणों से, संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले समूहों या वर्गों को शामिल करती है, तो यह सत्ता पर धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला होगा।"

37. विद्वान न्यायाधीशों द्वारा तैयार किया दूसरा प्रश्न था "क्या अनुच्छेद 16 (4) के से प्रावधान करने वाला एक कार्यकारी आदेश तुरंत लागू करने योग्य है?"

38. उपरोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध तर्क यह था कि अनुच्छेद 16 (4), सेवा में आरक्षण का प्रावधान आखिरकार मात्र एक सक्षम प्रावधान है और यह अपपश्चात आप में शक्ति का स्रोत नहीं है।यह तर्क दिया गया था कि जब तक उपयुक्त विधायिका द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है या अनुच्छेद 309 के परंतुक के संदर्भ में एक नियम के रूप में जारी नहीं किया जाता है, तब तक कार्यपालिका द्वारा इस तरह से बनाया गया "प्रावधान" प्रवर्तनीय नहीं हो जाता है।

39. इस तर्क को फिर से खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार कार्यकारी आदेश द्वारा अनुच्छेद 16 (4) के से आरक्षण का प्रावधान वैध रूप से किया जा सकता है, तो आवश्यक निहितार्थ से यह भी पालन करना चाहिए कि ऐसा प्रावधान बनाए जाने के क्षण से ही प्रभावी **है।नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून बनाम मोहनलाल मेहरोत्रा** ने (1992) **1 एस. सी. सी.** 20 में बताया कि इसे दोहराया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

> पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का निर्देश देने वाला कोई प्रशासनिक आदेश नहीं हो सकता है क्योंकि यह लागू वैधानिक

नियमों को बदल देगा।नियमों में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है।वास्तव में, यह आरक्षण के विषय पर चुप है।सरकार कार्यकारी आदेशों द्वारा आरक्षण का निर्देश दे सकती थी।प्रशासनिक आदेश वैधानिक नियमों के उल्लंघन में जारी नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसे वैधानिक नियमों के पूरक के रूप में जारी किया जा सकता है। संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1910)।वास्तव में इसी तरह के परिपत्र रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे जिसमें रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के चयन और गैर-चयन दोनों श्रेणियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई थी।उन्हें केंद्र सरकार की नीति को लागू करने के लिए जारी किया गया था और अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ, (1981) 1 एस. सी. सी. 246 में इस न्यायालय द्वारा उन्हें बरकरार रखा गया है।"

40. न्यायाधीशमूर्ति एस. रत्नावेल पांडियन ने एक अलग फैसले में, बहुमत से मत से सहमत होते हुए, उपरोक्त तैयार किए गए प्रश्न पर कहाः

(5) अनुच्छेद 16 (4) के से 'कोई भी प्रावधान' संसद या विधानमंडल द्वारा किया जाना जरूरी नहीं है।ऐसा प्रावधान एक कार्यकारी आदेश द्वारा भी

किया जा सकता है।"

41. इसी तरह, न्यायाधीशमूर्ति पी. बी. सावंत ने अपनी सहमति में बहुमत की स्थिति को दोहमता कि आरक्षण का प्रावधान या तो अधिनियम, नियम या यहां तक कि एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया जा सकता है।फैसले के पैरा 526 में न्यायाधीशमूर्ति सावंत ने कहाः

"526। अनुच्छेद 16 (4) की भाषा बहुत स्पष्ट है।यह राज्य को पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण के लिए एक "प्रावधान" करने में सक्षम बनाता है।यह प्रावधान या तो विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या इसके द्वारा बनाए गए नियम जो की कार्य या दोनों की अनुपस्थिति में कार्यकारी आदेश द्वारा किया जा सकता है ।कार्यकारी आदेश अनुच्छेद 13 (3) के से एक कानून से कम नहीं है जो अन्य चीजों के अलावा, आदेश, उपनियमों और अधिसूचनाओं को शामिल करने के लिए कानून को परिभाषित करता है।अनुच्छेद 16 (4) के से आरक्षण के प्रावधान राज्य के से भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित होने के कारण, वे संविधान के अनुच्छेद 309 से भी आते हैं।अनुच्छेद 309 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब तक उपयुक्त विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसकी ओर से प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक संघ या राज्य के से सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती

> और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है।इसके अग्रेतर जहां भी संविधान यह अपेक्षा करता है कि प्रावधान मात्र विधायिका के एक अधिनियम द्वारा किए जा सकते हैं, संविधान ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा है।उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 16 (3) के प्रावधान संसद द्वारा कानून बनाने की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों के विपरीत है जो राज्य को "कोई भी प्रावधान" करने की अनुमति देता है।इसी तरह, अनुच्छेद 302,304 और 307 में संबंधित विषयों पर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।"

42. यहां तक कि न्यायाधीशमूर्ति कुलदिप सिंह, जो आरक्षण के मुख्य मुद्दे पर अल्पसंख्यकों के साथ थे, ने भी आरक्षण का पक्ष लिया। उपरोक्त प्रश्न पर बहुमत।न्यायाधीशमूर्ति कुलदिप सिंह द्वारा तैयार किए गए इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने इस प्रकार दियाः

> "392. यह प्रश्न सहोदरन्यायाधीशों द्वारा जांच किया गया है और उन्होंने माना है कि आरक्षण संसद, राज्य विधानमंडल, वैधानिक नियमों के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।कार्यकारी

निर्देश तभी जारी किए जा सकते हैं जब इस विषय पर कोई वैधानिक प्रावधान न हो।वैधानिक प्रावधानों के पूरक के लिए कार्यकारी निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं जब वे प्रावधान आरक्षण के विषय पर चुप हों।कानून के ये प्रस्ताव असाधारण हैं और मैं इसे दोहराता हूं।यद्यपि मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि आरक्षण प्रदान करने वाला कोई भी कार्यकारी निर्देश (अनुच्छेद 16 (4), 73 या 162 के से जारी), जो सांविधिक वैधानिकों या अनुच्छेद 309 या किसी अन्य सांविधिक नियमों के विपरीत है, उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब तक कि यह सांविधिक वैधानिकों/नियमों के विपरीत है।"

43. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून की स्थिर स्थिति यह है कि सार्वजनिक सेवा में पदों और नियुक्तियों पर आरक्षण एक कार्यकारी आदेश द्वारा वैध रूप से किया जा सकता है, बशर्ते कि यह किसी भी वैधानिक नियमों या अधिनियम के साथ टकराव में न हो।

44. अब हम मुख्य प्रश्न पर आते हैं, जो यह है कि क्या सरकारी सेवा में आरक्षण के उद्देश्य से "अंदोलनकरियों" का वर्गीकरण एक वैध वर्गीकरण है और "अंदोलनकरियों" और उनके परिवार के सदस्यों या आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में किए गए आरक्षण को कानूनी रूप से बनाए रखा जा सकता है।

45. "पिछड़े वर्गों" या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षण एक ऐसा विषय है, जिसकी भारत के संविधान के से जांच की जानी चाहिए और प्रासंगिक प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 होंगे।हमें इस बात की भी जांच करनी होगी कि भारत के संविधान के से लोक सेवा में आरक्षण के विषय पर कानून ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और स्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में "आंदोलनकारी" कहां खड़े हैं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 ऐसे प्रावधान हैं जिन्होंने लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप इस विषय पर बहुत सारे निर्णय आए हैं।

46. मेरे विचार से समानता का अधिकार उस विषय की जड़ में निहित है जिससे निपटने के लिए हमें बुलाया गया है।समानता, या समानता की अवधारणा का हमारे संविधान के पूरे निकाय में एक प्रमुख उपस्थिति है।यदि भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला है, तो समानता संविधान और कानून के शासन की आधारशिला है।इसका कारण यह है कि समानता मात्र एक मौलिक अधिकार या हमारे संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है, बल्कि समानता, अन्य अधिकारों के विपरीत, अन्य आधार विशेषताओं का भी एक पहलू है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र।

3.Granville *ऑस्टिन-"भारतीय संविधानःएक राष्ट्र की आधारशिला"-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*

47. हमारे संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिए "स्थिति और अवसर की समानता" सुनिश्चित करने की घोषणा करती है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के से "समानता का अधिकार" यह आदेश देता है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में घोषणा की गई है कि "राज्य के से किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी"।हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) में यह प्रावधान है कि "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य यद्यपि मत में, राज्य के से सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।"

48. प्रारंभ में, लोक सेवा में आरक्षण के मामलों में, स्वीकृत स्थिति यह थी कि नियुक्तियां मात्र योग्यता के आधार पर की जानी थीं और इस नियम का एकमात्र अपवाद अनुच्छेद 16 के खंड (4) में था, जो राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में "नियुक्तियों या पदों" पर आरक्षण के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, यदि राज्य के से सेवा में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त अभ्यावेदन नहीं था।यह माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय का दृष्टिकोण बना रहा, और न्यायाधीशमूर्ति सुब्बा राव की एकमात्र असहमति के **साथ टी**. देवदासन[4] में दोहराया गया। यह असहमति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाद में देश का कानून बन गया।

4. टी. देवदासन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 17

49. जबकि टी. देवदासन में बहुमत ने इस बात को दोहराया कि सार्वजनिक रोजगार योग्यता पर आधारित है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मात्र संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के से बनाया गया एक अपवाद है, न्यायाधीशमूर्ति सुब्बा राव का विचार था कि यह अनुच्छेद 16 का खंड (4) नहीं है जो राज्य को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह शक्ति अनुच्छेद 16 के खंड (1) के से राज्य के पास है और अग्रेतर यह कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और इसे वही व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए जो "कानूनों के समान संरक्षण" के से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को दिया जा रहा है।

50. सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक निर्णय बाद में एन. एम. थॉमस[5] में आया, जो हमारे न्यायशास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 के बहुमत सेः2 ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद की प्रकृति में नहीं है, बल्कि यह मात्र अनुच्छेद का एक पहलू है 16 (1), जो "वंचित और वंचित वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष संदर्भ के साथ अवसर की समानता के विचार को बढ़ावा देता है और आगे बढ़ाता है।"अनुच्छेद 16 (1) फिर से अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धान्त का एक पहलू है, जो अनुच्छेद 14 की तरह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।देश भर के कई न्यायविदों की मत में, "थॉमस" सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के संबंध में न्यायिक विचार और प्रक्रिया में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।"थॉमस" के पश्चात मात्र वर्गों के लिए आरक्षण वैध रूप से किया जा सका जो "पिछड़े वर्गों" के अलावा अन्य थे।थॉमस के बिना सार्वजनिक रोजगार, स्वतंत्रता सेनानियों, शारीरिक रूप से विकलांग या रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए आरक्षण की कोई वैधता नहीं हो सकती थी।

5. केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एससीसी 310

51. अनुच्छेद 16 (1) "अवसर की समानता" की बात करता है।थॉमस के मामले में बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अवसर की सरल समानता को अनिवार्य नहीं करता है, बल्कि एक सार्थक यानी आनुपातिक समानता को अनिवार्य करता है "जो नागरिकों के एक वर्ग की अलग-अलग स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखता है जब भी वे स्थितियां और परिस्थितियां बुनियादी अधिकारों या दावों के रोजगार के लिए उनकी समान पहुंच के रास्ते में खड़ी होती हैं।इस बात पर जोर दिया गया कि मात्र तभी जब "अवसर की समानता" की अवधारणा को व्यापक अर्थों में समझा जाए, समाज में मौजूदा असमानता को ध्यान में रखते हुए यह सार्थक हो सकता है।माननीय न्यायाधीशमूर्ति मैथ्यू ने इस पर निम्नानुसार जोर दियाः-

> पीठ ने कहा, "मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुच्छेद 16 (4) की व्याख्या अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद के रूप में की जा सकती है, यदि अनुच्छेद 16 (1) में देखी गई अवसर की समानता एक निर्जल है, जो संख्यात्मक समानता की अवधारणा के लिए तैयार है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में नहीं रखती है।यदि अनुच्छेद 16 (1) के से गारंटीकृत अवसर की समानता का अर्थ प्रभावी भौतिक समानता है, तो अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है।यह मात्र यह बताने का एक जोरदार तरीका है कि अवसर की समानता को किस सीमा तक ले जाया जा सकता है।, यहां तक कि आरक्षण करने के बिंदु पर भी।"

52. थॉमस मामले में निर्धारित कानून देश का कानून है, जिसे

1992 में नौ-न्यायाधीशों में बहुमत द्वारा दोहराया गया था।

6.Thomas, प्रति मैथ्यू जे. पैरा 73

संविधान पीठ में इंद्र साहनी और अन्य **v. भारत संघ और अन्य ने** 1992 में **रिपोर्ट** के मामले।**(3) एससीसी** 217. इस पहलू पर निम्नलिखित प्रश्न (न्यायाधीशमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की बहुमत मत में) तैयार किए गए थे।

> 2. (क) क्या अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद है?
>
> (b) क्या अनुच्छेद 16 का खंड (4) उन विशेष प्रावधानों का संपूर्ण है जो 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' के पक्ष में किए जा सकते हैं?क्या यह उन विशेष प्रावधानों का संपूर्ण विवरण है जो सभी वर्गों, वर्गों या समूहों के पक्ष में किए जा सकते हैं?"
>
> (c) क्या अनुच्छेद 16 के खंड (1) के से आरक्षण दिया जा सकता है या क्या यह मात्र वरीयताओं/रियायतों के विस्तार की अनुमति देता है?"

53. बहुमत के अनुसार, अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद नहीं है, बल्कि यह "अंतर्निहित और खंड (1) द्वारा अनुमत वर्गीकरण का एक उदाहरण है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, लेकिन यह मात्र विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कहता है, जो अनुच्छेद 16 (1) में ही निहित है।अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान किए बिना भी, राज्य के पास अनुच्छेद 16 (1) के से ऐसी शक्तियां हैं।अनुच्छेद 16 (4) मात्र पिछड़े वर्गों के लिए जोर देता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में पहले से ही है।

54. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, थॉमस में पहली बार यह निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का एक पहलू है, और अनुच्छेद 14 की तरह

यह भी उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने की शक्तियां वास्तव में अनुच्छेद 16 के खंड (1) के से आती हैं।इंदिरा साहनी के बहुमत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा थॉमस में लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> "हमारी सम्मानजनक मत में, थॉमस में बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।हम भी मानते हैं कि अनुच्छेद 16 (1) अपने द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है।ऐसा न करने से असमानता बढ़ेगी और बढ़ेगी।अनुच्छेद 16 (4) इस तरह के वर्गीकरण का एक उदाहरण है, जिसे मामले को विवाद के बाद रखने के लिए रखा गया है।"नागरिकों के पिछड़े वर्ग" को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो राज्य की सेवा में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण की प्रकृति में विशेष उपचार के योग्य है।तदनुसार, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद नहीं है।यह खंड (1) में निहित और अनुज्ञात वर्गीकरण का एक उदाहरण है।संविधान सभा में अनुच्छेद 10 (3) [अनुच्छेद 16 (4) के अनुरूप] के मसौदे पर बहस के दौरान डॉ. अम्बेडकर का भाषण-पैरा 693 में संदर्भित
>
> - यह दर्शाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की एक

बड़ी संख्या ने "कुछ समुदायों के प्रवेश के लिए प्रावधान (किया जा रहा है) जो अब तक प्रशासन से बाहर रहे हैं" पर जोर दिया और उस मसौदे खंड (3) को उक्त मांग की मान्यता और स्वीकृति में रखा गया था।यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे खंड (1) के साथ और उसके अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।वास्तव में, खंड (4) के बिना भी, राज्य के लिए यह अनुज्ञेय होता कि उसने ऐसा वर्गीकरण विकसित किया होता और

> उनके पक्ष में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण का प्रावधान।खंड (4) मात्र विशिष्ट शब्दों में मामले को किसी भी संदेह के बाद रखता है।"

55. इस प्रश्न के लिए कि क्या अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अवधारणा का संपूर्ण है, इसका उत्तर यह था कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) उन विशेष प्रावधानों का संपूर्ण है जो "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" के पक्ष में किए जा सकते हैं अग्रेतर यह कि "पिछड़े वर्गों को स्वयं संविधान द्वारा विशेष व्यवहार के योग्य वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है अग्रेतर संविधान ने स्वयं विशेष व्यवहार की प्रकृति को निर्दिष्ट किया है, यह माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अलावा या उसके बाहर उनके पक्ष में कोई अग्रेतर वर्गीकरण या विशेष व्यवहार की अनुमति नहीं है"।

56. प्रश्न 2 (ग), जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह <u>था कि क्या अनुच्छेद 16 (4) आरक्षण की अवधारणा का संपूर्ण विवरण</u> है।चूँकि इस प्रश्न के लिए बहुमत द्वारा दिए गए उत्तर का हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसलिए हमें पूरे उत्तर को पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत करना चाहिए, जो नीचे दिया गया हैः

> 744 , "विचार करने के लिए अगला पहलू यह है कि क्या खंड (4) आरक्षण की अवधारणा का संपूर्ण है?दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 16 के प्रश्न (1) के से प्रश्न (4) के बाहर कोई आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।इस विषय में दो मत हैं।मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने पर, हमारी मत है कि खंड (4) निम्नलिखित अवधारणा का संपूर्ण नहीं है और न ही माना जा सकता है - ; यह

केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का संपूर्ण है।मात्र इसलिए कि वर्गीकरण के एक रूप को एक विशिष्ट खंड के रूप में बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि खंड (1) में निहित वर्गीकरण की अवधारणा और शक्ति समाप्त हो जाती है।ऐसा कहना सिद्धान्त रूप में सही नहीं होगा।लेकिन इसके साथ ही एक बात स्पष्ट है।यह बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में है-अग्रेतर सभी अग्रेतर विभिन्न कारणों से नहीं-कि खंड (1) के से किसी भी प्रकार के अग्रेतर आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में, यदि आह्वान किया जाता है, तो राज्य को संतुष्ट करना होगा कि किसी विशिष्ट स्थिति के निवारण के लिए ऐसा प्रावधान करना (जनहित में) आवश्यक था।खंड (4) की उपस्थिति को विशेष उपचार के योग्य अग्रेतर अधिक वर्ग बनाने की प्रवृत्ति पर एक बाधा के रूप में कार्य करना चाहिए।ऐसा कहने का कारण बहुत सरल है।यदि खंड (4) के साथ-साथ खंड (1) दोनों के से आरक्षण किया जाता है, तो मुक्त प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को तदनुसार समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसा करना उचित नहीं है।"

(महेत्व दिया गया)

57. इसलिए इस विषय पर जो कानून है, मेरी मत में उसे इस प्रकार कहा जा सकता हैः

"पिछड़े वर्गों" के लिए लोक सेवा में आरक्षण केवल संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत किया जा सकता है। फिर भी, नागरिकों के अन्य वर्गों या वर्ग (जिनके साथ हम वर्तमान में संबंधित हैं) के लिए, राज्य के पास संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के से आरक्षण देने की शक्तियां हैं।फिर भी चूंकि ये असाधारण शक्तियाँ हैं, इसलिए आवश्यक निहितार्थ से इनका उपयोग "बहुत ही असाधारण परिस्थितियों" में किया जाना चाहिए।हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोर दिए गए इस बिंदु को दोहराना चाहिए कि "यह बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में है,-सभी और विभिन्न कारणों से नहीं-कि खंड (1) के से किसी भी प्रकार के अग्रेतर आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए।"अग्रेतर अगर इस तरह के आरक्षण किए जाते हैं तो यह संतोषजनक होना चाहिए कि ऐसा आरक्षण आवश्यक था और जनहित में किया गया है।

58. 2004 में क्या असाधारण स्थिति थी, जिसमें "आंदोलनकारियों" के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के माध्यम से निवारण की आवश्यकता थी, और क्या यह जनहित में था!

59. उत्तराखंड सरकार के एक अतिरिक्त सचिव (गृह) द्वारा शपथ लिए गए अपने जवाबी शपथ पत्र में राज्य ने "अंदोलनकरियों" को आरक्षण देने के लिए लिए गए निर्णय के संबंध में घटनाओं के क्रम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं।

60. जवाबी शपथ पत्र के पैरा 5 में कहा गया हैः

> 5) उत्तराखंड राज्य का निर्माण पहाड़ी राज्य के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लंबे आंदोलन के पश्चात 09/11/2000 पर किया गया था।पहाड़ी राज्य के

निर्माण पश्चात राज्य के विभिन्न हिस्सों से मांग की गई थी कि नए राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित उपचार दिया जाए।04 अगस्त 2004 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया था - प्रधान सचिव कार्मिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव के प्रतिनिधि, अतिरिक्त सचिव कार्मिक और अतिरिक्त सचिव गृह ने उत्तराखंड के आंदोलनकारी को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बैठक में भाग लिया।विस्तृत चर्चा के पश्चात उक्त बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि गृह विभाग द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात नए राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन के दौरान घायल हुए या जेल गए उत्तराखंड के आंदोलनकारी को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।इस बात पर भी सहमति बनी कि आंदोलनकारियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंः-

1. जो घायल/आंदोलनकारी 7 या अधिक दिनों से जेल में थे, उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी जो लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर हैं।
2. 7 दिन से कम समय तक जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति, 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज और अगले 5 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
3. 7 दिन से कम समय तक जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को स्व-रोजगार योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
4. आंदोलनकारियों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान पत्र दिया जाएगा।
5. उक्त पहचान पत्र रखने वाले आंदोलनकारियों को राज्य के विधानसभा सचिवालय में प्रवेश के लिए पास देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही पर 7 अगस्त 2004 को तब के माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी ली गई थी।"

61. उपरोक्त बैठकों के परिणामस्वरूप, दो सरकारी आदेश दिनांक 1

(2004 का जी. ओ. संख्या 1269 और 2004 का 1270) पारित किए गए।इसके बाद, दिनांक 25.08.2005 को, सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि 7 दिनों की अवधि के दौरान

जेल में बचे "आंदोलनकरियों" की गिनती की जानी थी और यह स्पष्ट किया गया था कि प्रभावी तिथि वह तिथि होगी जब संबंधित मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था।सरकारी आदेश दिनांक 08.11.2006 के अनुसार, क्षैतिज आरक्षण का लाभ ऐसे "आंदोलनकरियों" के आश्रितों और परिवार के सदस्यों को दिया गया था, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी या कुछ कारणों से उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सका था।बाद में, सरकारी आदेश दिनांक 13.12.2011 के माध्यम से यह लाभ परिवार के सभी सदस्यों और "अंदोलनकरियों" के आश्रितों को दिया गया।22.10.2008 पर, एक और सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें मानदंड निर्धारित किए गए थे कि एक "आंदोलनकारी" की पहचान कैसे की जानी चाहिए।इस सरकारी आदेश के अनुसार, स्थानीय खुफिया इकाई (एल. आई. यू.) की रिपोर्ट के आधार पर या पुलिस विभाग में उपलब्ध किसी अन्य रिपोर्ट के आधार पर एक "आंदोलनकारी" की पहचान की जानी थी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट और किसी भी अन्य रिपोर्ट की प्रति शामिल होगी जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

62. इस न्यायालय के समक्ष राज्य का तर्क, नियुक्तियों और "आन्दोलनकरियों" के पक्ष में किए गए आरक्षण के औचित्य में, यह होगा कि राज्य ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान पीड़ित लोगों को ऐसा लाभ देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया, क्योंकि विभिन्न वर्गों से इस तरह के आरक्षण की मांग की गई थी।राज्य के विद्वान महाधिवक्ता का तर्क होगा कि अंततः यह सरकार द्वारा लिया एक नीतिगत निर्णय था, क्योंकि सरकार ने "आंदोलनकरियों" को सार्वजनिक सेवा में इस तरह का आरक्षण देना सबसे अच्छा समझा।हम लोक सेवा में आरक्षण देने की सरकार की शक्तियों पर विवाद नहीं करते हैं।यह देखना होगा कि क्या ये नियुक्तियां

और आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध हैं।

63. हम एक असमान समाज में रहते हैं। हमारे समाज में व्याप्त अन्य असमानताओं के साथ साथ स्थिति, अवसर, परिस्थितियों और वर्ग की असमानता है, इसका मतलब यह होगा कि एक ही कानून सभी की समान रूप से रक्षा नहीं कर सकता है।इसलिए केवल कानून में समानता वास्तविक समानता नहीं है।न्यायाधीशमूर्ति मैथ्यू ने "थॉमस" के मामले में समानता की व्यापक अवधारणा को समझाते हुए प्लेटो की एक टिप्पणी का उपयोग किया था, जो यह है कि "एक पूरी तरह से सरल सिद्धान्त को कभी भी उस स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है जो सरल के विपरीत है।[7] इस कारण द्वारा, भारत के संविधान ने समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए, समाज के कमजोर वर्गों को ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम द्वारा समानता के अधिकार को एक उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और प्रभावी अधिकार बना दिया, जो एक समान अवसर पैदा करेंगे।कानूनों के समान संरक्षण का मतलब ठीक यही है। "कानूनों के समक्ष समानता" का ठीक यही अर्थ है। अनुच्छेद 14 केवल "कानूनों के समक्ष समानता, का प्रतीक नहीं है, बल्कि अधिक विचारशील और सार्थक रूप से, यह "कानूनों के समान संरक्षण" को अनिवार्य करता है।संक्षेप में, संविधान एक औपचारिक समानता नहीं बल्कि एक वास्तविक, मूल और उद्देश्यपूर्ण समानता प्रदान करता है, जो हमारे समाज में विशाल सामाजिक और आर्थिक मतभेदों से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है।

64. "कानूनों के समान संरक्षण" की इस अवधारणा में सन्निहित, वर्गीकरण का सिद्धांत निहित है।इसका मतलब है कि मात्र ऐसे व्यक्तियों के लिए कानूनों का समान संरक्षण जो समान रूप से स्थित हैं।इसलिए कानून उन लोगों के बीच भेदभाव करता है जो समान रूप से स्थित हैं और जो नहीं

हैं।फिर भी, इस भेद को कानून में मान्य बनाने के आदेश, दो शर्तों को पूरा करना होगा।वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से समूह को बाकी से एक के रूप में वर्गीकृत करता है और दूसरा, वर्गीकरण में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक तर्क होना चाहिए।अन्य शब्दों में, वर्गीकरण का एक वैध और वैध उद्देश्य भी होना चाहिए।वर्गीकरण कानून में अनुमत होना चाहिए क्योंकि एक अस्वीकार्य वर्गीकरण समानता और कानूनों के समान संरक्षण का सिद्धान्त का उल्लंघन करेगा

---

7. थॉमस (ऊपर) पैरा 52।

ए. आई. आर. **1955 एस. सी. 191 में रिपोर्ट** किए गए **बुधन चौधरी बनाम बिहार** राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 की उपरोक्त अवधारणा को निम्नानुसार समझायाः

> "5.. अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को मना करता है, यह कानून के उद्देश्यों के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है।यद्यपि अनुज्ञेय वर्गीकरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आदेश दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात्, (i) वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं, और (ii) उस अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्नगत अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर स्थापित किया जा सकता है; अर्थात्, भौगोलिक, या वस्तुओं या

व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार। आवश्यक यह है कि एक होना ही चाहिए वर्गीकरण के आधार और के बीच संबंध विचाराधीन अधिनियम का उद्देश्य . यह है न्यायालय के निर्णयों से यह भी अच्छी तरह से स्थापित होता है कि अनुच्छेद 14 न मात्र एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है।"

65. चूंकि आरक्षण का स्रोत जिसके बारे में हम चिंतित हैं, वह संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में निहित है, जो और कुछ नहीं बल्कि अनुच्छेद 14 का एक पहलू है, इसलिए यह देखना होगा कि क्या आरक्षण के उद्देश्यों के लिए "अंडोलनकरों" को एक अलग वर्ग बनाना कानून में मान्य है?

66. यह आरक्षण मुख्य रूप से वर्ष 2004 में दो सरकारी आदेशों के माध्यम से किया गया है, जिसे हम जी. ओ. संख्या 1269/2004 और 1270/2004 के रूप में संदर्भित करेंगे।जी. ओ. नं. से तहत। 69, सरकारी सेवा में एक बार का आरक्षण उन "आंदोलनकरियों" को दिया जाता है जो या तो "घायल" हुए थे या 7 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहे थे।यह सरकारी सेवा में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों में एक बार के आरक्षण के लिए था, जो राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर हैं। जी. ओ. सं. 1270, जिसे जी. ओ. सं. 1269 (यानी 11.08.2004) के रूप में उसी तिथि को पारित किया गया था, सरकारी सेवा में उन "आंदोलनकारियों" के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण किया गया था जिन्हें 7 दिनों से कम समय के लिए जेल में रखा गया था।बमुश्किल कुछ वर्षों के बाद, इस आरक्षण को न मात्र "अंदोलनकरियों" के लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी बढ़ाया गया था।मेरे विनम्र लेकिन सुविचारित दृष्टिकोण में, यह वर्गीकरण अपने आप में एक से अधिक तरीकों से त्रुटिपूर्ण है।एक "अंदोलनकारी" जो 7 दिनों तक जेल में रहा था, उसे किसी भी चयन या प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना नौकरी मिल जाती है (जी. ओ. संख्या 1269/2004 दिनांक 11.08.2004 के अनुसार), जबकि "अंदोलनकारी" जो इसी तरह 6 दिनों के लिए जेल में है, उसे सरकारी सेवा में स्वतः प्रवेश नहीं मिल सकता है (जी. ओ. संख्या 1270/2004 दिनांक 11.08.2004)।उसे अभी भी एक प्रतियोगिता का सामना करना होगा।इसके अलावा, एक "अंदोलनकारी" जो घायल हो गया है, उसे वही लाभ मिलता है जबकि एक "अंदोलनकारी" जो 6 दिनों तक जेल में रहा था, उसे नहीं मिलता है।इसके अग्रेतर "चोट" से हमारा वास्तव में क्या मतलब है, यह परिभाषित नहीं किया गया है।कानून में चोट की वास्तव में एक व्यापक परिभाषा हो सकती है।भले ही हम यह मान लें कि कार्यपालिका का जो मतलब था वह भारतीय दंड संहिता में परिभाषित चोट थी, वह भी मामले में मदद नहीं करता

है।भारतीय दंड संहिता के से "चोट" को खंड 44 परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

> "44. **'चोट'।- "चोट" शब्द** किसी भी व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या सम्पति में अवैध रूप से किए गए किसी भी नुकसान को दर्शाता है।"

67. भले ही हम "घाव" शब्द को "चोट" शब्द के पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, हम पाते हैं कि इसका भी बहुत व्यापक अर्थ है। आई. पी. सी. की धारा 319[8] "चोट" को परिभाषित करती है और आई. पी. सी. की धारा 320[9] "गंभीर चोट" को परिभाषित करती है, जो शारीरिक दर्द से लेकर फ्रैक्चर या हड्डी के विस्थापन, सिर या चेहरे की स्थायी विकृति या किसी भी आंख की दृष्टि के स्थायी अभाव का कारण बनने वाली किसी भी चीज़ के बीच कुछ भी होगी।इसलिए, तार्किक रूप से एक व्यक्ति जिसे "शारीरिक दर्द" का सामना करना पड़ा है, एक "आंदोलनकारी" के रूप में बिना किसी प्रतिस्पर्धा का सामना किए सरकारी सेवा का हकदार है, जबकि एक अन्य "आंदोलनकारी" जो 6 दिनों तक जेल में रहा, वह समान रूप से हकदार नहीं है।इसके अलावा, शारीरिक दर्द का वास्तव में क्या प्रमाण है!एक वर्गीकरण को वैज्ञानिक या गणितीय रूप से सटीक होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि विशेष अदालत विधेयक, 1978, पुनः (1979) 1 एस. सी. सी. 380 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, फिर भी यह उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए।

68. उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घायल होने के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए पात्र बनाना, बिना सटीक या उचित रूप से परिभाषित किए कि "चोट" क्या है, पूरे प्रावधान को अस्पष्ट बनाता है।यह दुरुपयोग के लिए भी खुला है।किसी को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान

मामले में भी करुणेश जोशी (2007 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 945 में याचिकाकर्ता) अपने दावे के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे कि वे 29.09.1995 पर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान "घायल" हुए थे।

---

8. "319। **चोट लगी।- जो** भी किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता का कारण बनता है, उसे चोट पहुँचाने वाला कहा जाता है।"

9. "320। **गंभीर चोट लगी।-** निम्नलिखित प्रकार की चोटों को मात्र "गंभीर" के रूप में नामित किया गया है:-

सबसे पहले।- नपुंसकता

दूसरा।- दोनों आँखों की दृष्टि का स्थायी संरक्षण।तीसरी बात।- किसी *भी*

कान की सुनवाई का स्थायी अभाव।चौथा।- किसी भी सदस्य *या* संयुक्त

का निजीकरण।

पाँचवाँ।- किसी की शक्तियों का विनाश या स्थायी हानि
संयुक्त सदस्य।

छठा।- सिर या चेहरे का स्थायी विरूपण।

सातवाँ।- हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या विस्थापन।

आठवीं।कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित बीस दिनों के अंतराल के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द में रहता है, या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ होता है।"

घटना का कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि उक्त दिन उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने के दौरान याचिकाकर्ता पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गया था।इसके बाद उन्होंने रिट याचिसे के पैरा 5 में कहा कि वे लाठी चार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और हल्द्वानी में डॉ. पी. सी. हरबोला नामक एक निजी डॉक्टर के इलाज पर चल रहे थे।अपने तर्क को साबित करने के, उन्होंने दिनांकित 28.10.1995 डॉक्टर का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो नीचे दिया गया हैः-

> "यह प्रमाणित है कि श्री के. जोशी, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं, से मेरे द्वारा शाम 6 बजे 29-09-1995 पर इलाज किया गया है। वह चोट के इलाज के लिए 29-09-1995 से 29-10-1995 तक मेरे इलाज में रहे।उनके ऊपरी और निचले अंगों और पीठ की चोटों का मेरे द्वारा इलाज किया जाता है।"

69. याचिकाकर्ता को क्या चोट लगी थी, यह डॉक्टर द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।बस इतना ही कहा जा सकता है कि श्री करुणेश जोशी का "ऊपरी और निचले अंगों और पीठ की चोटों" के लिए इलाज किया जा रहा था।क्या यह "चोट" का एक वैध प्रमाण हो सकता है?शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि "चोट" को परिभाषित नहीं किया गया है!इतना ही नहीं, हालाँकि सरकारी आदेश 11.08.2004 का है, और उसके बाद नियम 20.05.2010 पर बनाए गए थे, फिर मात्र नियमों में मात्र, राज्य द्वारा सटीक रूप से परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि "क्षति" क्या है।इसलिए,

"अंडोलंकरी" का वर्गीकरण, जो आत्यन्तिक रूप से अस्पष्ट पहचान पर आधारित है, एक उचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता है।

70. वर्गीकरण का सिद्धांत एक न्यायाधीश द्वारा बनाया गया सिद्धांत है, जिसे न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला द्वारा हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में बनाया और शामिल किया गया है।राज्य वर्गीकरण के आधार पर मात्र तभी कानून बना सकता है जब वर्गीकरण में एक बोधगम्य अंतर और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्क हो।मेरी मत में, बाकी से "आन्डोलंकरी" का वर्गीकरण किसी भी उचित मानदंड पर आधारित नहीं है।"जेल में 7 दिन और उससे अधिक" और "जेल में 7 दिनों से कम" का अंतर भी उचित नहीं है।

71. जैसा कि हमने पहला सरकारी आदेश देखा है। जी. ओ. नं. 1269/2004 पदों को भी आरक्षित नहीं करता है, लेकिन तुरंत घोषणा करता है कि जो कोई भी "आंदोलनकारी" है यानी जिसे या तो चोट लगी है या जो 7 दिनों से अधिक समय तक "आंदोलन" के दौरान जेल में रहा है, उसे बिना किसी प्रतियोगिता या परीक्षा का सामना किए अपनी योग्यता के आधार पर सीधे श्रेणी 3 या श्रेणी 4 का पद मिलेगा।दूसरे शब्दों में, सभी श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पद जो उस समय खाली थे, मात्र "अंदोलनकरियों" द्वारा भरे जा सकते थे यदि ऐसे पदों के लिए आवश्यक संख्या में "अंदोलनकरियों" होते। 10 प्रतिशत का वास्तविक आरक्षण एक अन्य सरकारी आदेश अर्थात जी. ओ. सं. 1270/2004 में किया गया है, जो सभी स्तरों पर सभी सरकारी पदों के लिए10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बनाता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यहां 10 प्रतिशत पदों पर आरक्षण केवल श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों के लिए नहीं है, बल्कि यह पहली से चौथी श्रेणी के सभी पदों के लिए लागू है, चाहे वे राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर हों या इसके दायरे में हों।

72. "अंदोलनकरियों" को अन्य कारणों से भी किसी भी बोधगम्य

भेद के आधार पर एक अलग वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है।"अंदोलनकारी" की परिभाषा के तहत एक व्यक्ति जो 24 घंटे या यहां तक कि एक महीने के लिए भी पुलिस हिरासत में रहा है। आंदोलन के दौरान कुछ घंटे या कोई शारीरिक पीड़ा प्राप्त करने वाले आरक्षण के हकदार हैं, जबकि कई अन्य जो आंदोलन में भाग लेते थे, "धरना" "हड़ताल" पर बैठते थे, अपने समय की कीमत पर लंबे जुलूसों, पूर्वाभ्यासों आदि में भाग लेते थे, पढ़ाई और काम को "आंदोलनकारी" की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है, हालांकि उन्हें भी "आंदोलनकारी" कहे जाने का उतना ही अधिकार है जितना कि आंदोलन के दौरान कुछ घंटों तक जेल में रहने वाले या "आहत" होने वाले को है।

73. "वर्गीकरण" के इस सिद्धांत पर अधिक जोर देना भी प्रतिकूल हो सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एल. आई. सी. ऑफ **इंडिया बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (1995) के** मामले में **जोर दिया था।** 5 एससीसी 482।उपरोक्त निर्णय में, "वर्गीकरण" पर अधिक जोर देने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निम्नानुसार कहना पड़ाः

> "।वर्गीकरण का सिद्धांत मात्र एक सहायक नियम है जिसे अदालतों द्वारा समानता के सिद्धांत को व्यावहारिक सामग्री देने के लिए विकसित किया गया है, वर्गीकरण के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर दिया गया है या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने के लिए चिंतित या निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अदृश्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की गौरवशाली सामग्री की गहरी शक्ति को नष्ट कर सकता है।वर्गीकरण पर अत्यधिक

जोर देने से अनिवार्य रूप से वर्गीकरण के सिद्धांत को समानता के सिद्धांत और संविधान की प्रस्तावना के स्थान पर रखा जाएगा जो संविधान का एक अभिन्न अंग और योजना है।"

---

74. इससे पहले मोहम्मद.शुजात अली **बनाम भारत संघ ने ए. आई. आर.** 1974 एस. **सी. 1631 में बताया** कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को वर्गीकरण के सिद्धांत पर अधिक जोर देने पर निम्नानुसार कहना थाः

> "वर्गीकरण के सिद्धांत पर अधिक जोर देना या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का एक चिंतित और निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से इसकी विशिष्ट सामग्री की समानता की गारंटी से वंचित कर सकता है।"

75. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता संविधान सभा की बहस के दौरान डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अलावा किसी और द्वारा नहीं उठाई गई चिंता के समान है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) में "पिछड़े" शब्द को शामिल करने को उचित ठहराते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने आगाह किया था कि "जब तक आप" पिछड़े "के रूप में कुछ योग्यता वाले वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं, तब तक आरक्षण के पक्ष में किया गया अपवाद अंततः नियम को पूरी तरह से खा जाएगा।नियम का कुछ भी नहीं रहेगा।नियम यह है कि "राज्य के से किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी" (अनुच्छेद 16 का खंड 1)।

76. हस्तक्षेप करने वालों के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश चंद्र पंत ने इस अदालत के समक्ष यह समझाने के लिए बहुत मेहनत की कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में एक अलग राज्य के लिए आंदोलन या "आंदोलन" मात्र एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक अत्यंत व्यापक आंदोलन था, जो वर्तमान उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था।यह कस्बों या शहरी

क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उप-मंडलों और गाँवों में कभी-कभी और भी अधिक गहराई तक प्रवेश कर गया था। वर्ष 1994-1995 में जब आंदोलन अपने चरम पर था, उत्तराखंड में हर जगह "धरना", सड़क मार्च और सार्वजनिक सभाएं आम थीं।इसलिए, अगर सपना जिसे "उत्तराखंड" कहा जाता है, अंततः एक वास्तविकता बन सकता है, यह उत्तराखंड के सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों के कारण था।यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हर जगह महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं।उन्हें न मात्र कई स्थानों पर "लाठी चार्ज" और पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा, बल्कि उनमें से दो, श्रीमती. बेलमती चौहान और श्रीमती. हंसा धनाई को उत्तराखंड आंदोलन के चरम के दौरान मसूरी में "झूला घाट" पर गोली मार दी गई थी।निश्चित रूप से यदि आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी, तो यह प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले के लिए ऐसे "आंदोलनकारियों" के लिए तैयार की गई सूची में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

77. इस रिट याचिका में, उत्तराखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव (गृह) श्री मंजुल कुमार जोशी द्वारा जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया है, जिन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि आरक्षण का लाभ सभी को नहीं दिया गया था, बल्कि सरकारी आदेश संख्या 1269/2004 और 1270/2004 में एक मानदंड निर्धारित किया गया था।13 जिलों के सभी जिलाधिकारियों को सूचना भेजी गई और उन्हें मात्र ऐसे "आंदोलनकारियों" की सूची तैयार करने के लिए कहा गया जो या तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घायल हो गए थे या जेल में रह गए थे और सरकार के इन आदेशों का पालन करते हुए, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों ने चिह्नित "आंदोलनकारियों" की एक सूची तैयार की और मात्र ऐसे व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को ही आरक्षण का लाभ

दिया जाएगा।ये सूचियाँ जो संलग्नक संख्या 15 से 26 के भाग के रूप में जवाबी शपथ पत्र के साथ संलग्न की गई हैं, उनमें उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के लिए चिह्नित "आंदोलनकारियों" की सूची है।

78. इन सूचियों के अवलोकन से पता चलता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना खराब रहा है।उत्तराखंड के 13 जिलों के लिए तैयार की गई ये सूचियां उत्तराखंड में उनकी भागीदारी के स्तर के साथ न्याय नहीं करती हैं। पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में महिलाओं का कोई प्रत्यावेदन नहीं है।"चिह्नित आंदोलनकारियों की इन सूचियों में किसी भी महिला का नाम नहीं है।शेष जिलों में भी महिलाओं का प्रत्यावेदन बेहद कम है। उदाहरण के लिए, रुद्रप्रयाग जिले के लिए चिह्नित 188 "आंदोलनकारी" में से मात्र एक महिला है। इसी तरह जिला चमोली के लिए चिह्नित 826 "आंदोलनकारीयों" में से मात्र 74 महिलाएँ हैं, जिला टिहरी गढ़वाल के लिए चिह्नित 464 " आंदोलनकारीयों " में से मात्र 26 महिलाएँ हैं, जिला चंपावत के लिए चिह्नित 249 " आंदोलनकारीयों" में से मात्र 10 महिलाएँ हैं, जिला बागेश्वर के लिए चिह्नित 72 " आंदोलनकारीयों " में से मात्र 1 महिला है, जिला अल्मोड़ा के लिए चिह्नित 220 " आंदोलनकारीयों" में से मात्र 4 महिलाएँ हैं। इसी तरह, देहरादून जिले में " आंदोलनकारीयों" के कोटे के से कार्यरत कुल 164 व्यक्तियों में से एक भी महिला नहीं है, उत्तरकाशी जिले में कार्यरत 65 व्यक्तियों में से एक भी महिला नहीं है, नैनीताल जिले में कार्यरत 15 व्यक्तियों में से महिला का कोई प्रत्यावेदन नहीं है, और फिर हरिद्वार जिले में 3 नियोजित व्यक्तियों में से महिला का कोई प्रत्यावेदन नहीं है।

79. उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि हालांकि उत्तराखंड आंदोलन में महिलाएं सबसे आगे थीं, लेकिन उन्हें "चिह्नित अंडोलनकरियों" के रूप में बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो मात्र यह साबित करता है कि

"अंडोलनकरियों" के लिए तैयार की गई सूची या तो मनमाना है या उचित मानदंडों पर आधारित नहीं है।

80. यहाँ यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सूची में महिलाओं का उचित अभ्यावेदन अपने आप में वर्गीकरण को उचित नहीं ठहराएगा।फिर भी यह इस मामले में सरकार की मनमानी को दर्शाता है और इससे भी अधिक यह पता चलता है कि "वर्गीकरण" त्रुटिपूर्ण है।

81. "अंदोलनकरियों" की तुलना "स्वतंत्रता सेनानियों" से करने का प्रयास किया गया है।तर्क यह है कि चूंकि सरकारी सेवा में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नियुक्तियों और पदों का आरक्षण वैध है, इसलिए "आंदोलनकारियों" के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए।इस मुद्दे पर हमारे सामने सबसे करीबी उद्धरण डी. एन. **चंचला बनाम मैसूर राज्य और अन्य का है, जिसकी** सूचना 1971 **(2) एस. सी.** सी. 293 में दी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से (न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ की असहमति) "राजनीतिक पीड़ितों" (स्वतंत्रता सेनानियों के समान) के आश्रितों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों के आरक्षण को वैध ठहराया था।

82. उपरोक्त मामले में, पूर्ववर्ती मैसूर राज्य (वर्तमान कर्नाटक) अन्य बातों के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों में राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिए आरक्षण दिया था।याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका के माध्यम से उन नियमों को चुनौती दी थी जिनके द्वारा ये आरक्षण दिए गए थे।आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (4) के से किया गया था, जो एक ऐसा प्रावधान है जो राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।उपरोक्त मामले में बहुमत की मत थी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक पीड़ितों द्वारा झेली गई पीड़ाओं के कारण राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित "पिछड़े वर्ग" से संबंधित हैं।उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पहला तर्क था कि "राजनीतिक पीड़ित" की परिभाषा अस्पष्ट थी।इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि "राजनीतिक पीड़ित" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे कम से कम "छह महीने" की अवधि के लिए कारावास या निरोध के रूप में कारावास का सामना करना पड़ा है

या जिसे मृत्यु दण्ड दिया गया है, या वास्तव में निरोध में या कारावास से गुजरते हुए उसकी मृत्यु हो गई है, या पुलिस या सेना द्वारा गोलीबारी या लाठी चार्ज से स्थायी रूप से मार दिया गया है या अक्षम कर दिया गया है, या नौकरी खो दी है।

सम्पति या आजीविका के अन्य साधन।इसलिए राजनीतिक पीड़ित की परिभाषा को अस्पष्ट नहीं माना गया।जहां तक वर्गीकरण की तर्कसंगतता का संबंध है, बहुमत ने राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें रक्षा कर्मियों के आश्रितों के साथ तुलना करके और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> "अनुच्छेद 15 (4) में अंतर्निहित सिद्धान्त यह है कि एक तरजीही उपचार वैध रूप से दिया जा सकता है क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसकी आवश्यकता है, ताकि समय के साथ वे समाज के अधिक उन्नत वर्गों के साथ समान स्थिति में खड़े हो सकें।यह किसी भी तरह से अनुचित नहीं होगा यदि यह सिद्धान्त उन लोगों पर भी लागू किया जाए जो विकलांग हैं लेकिन अनुच्छेद 15 (4) के से नहीं आते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिद्धान्त पर ही रक्षा कर्मियों और पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षण बरकरार रखा गया है।इस तरह के आरक्षण के लिए मानदंड यह है कि रक्षा बलों में सेवारत लोग या जिन्होंने इस तरह से सेवा की थी, वे अपने बच्चों को शिक्षा देने में नुकसान में हैं और थे क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कठिन स्थानों पर रहना पड़ता था, जहां कहीं और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और उपलब्ध नहीं थीं।हमारे विचार में, उन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए उस सिद्धान्त का विस्तार करना अनुचित नहीं है जो मुक्ति संग्राम में अपनी भागीदारी के परिणामस्वरूप जीवन में अस्थिर हो गए थे; कुछ मामलों में आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे, और

इसलिए, अपने बच्चों को शिक्षा का वह वर्ग उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे जो उन्हें उन लोगों के बच्चों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में डाल देगा जो उस नुकसान से पीड़ित नहीं थे।यदि ऐसा है, तो इसका पालन करना चाहिए 'राजनीतिक पीड़ित' की परिभाषा न मात्र ऐसे पीड़ितों के बच्चों को दूसरों से अलग करती है, बल्कि इस तरह के वर्गीकरण का नियमों के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जो सीटों के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है।"

83. फिर भी, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) से संबंधित है। अनुच्छेद 15 (1) के अपवाद के रूप में अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) से संबंधित नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) से संबंधित है, जहाँ दावा किए गए आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर नहीं हैं, बल्कि इस आधार पर हैं कि "आंदोलनकारी" एक अलग यद्यपि विशिष्ट वर्ग का गठन करते हैं।इसके अलावा, और जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के लिए आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सरकारी सेवा में आरक्षण दिया जा रहा है।"आंदोलनकारियों" को न तो "पिछड़े वर्ग" के रूप में माना और न ही यह उनका दावा है, वास्तव में यह विद्वान महाधिवक्ता या श्री रमन कुमार शाह का तर्क भी नहीं है।उनका मामला एक विशेष और अलग श्रेणी का है।इसलिए, उक्त निर्णय (डी. एन. चंचला बनाम मैसूर राज्य और अन्य) "अंदोलनकरियों" के लिए कोई मददगार नहीं है।

84. किसी भी मामले में, मेरी सुविचारित मत में "अंदोलनकरियों" की तुलना "स्वतंत्रता सेनानियों" के साथ एक वैध तुलना नहीं है।स्वतंत्रता सेनानी वह होता है जिसे स्वतंत्रता संग्राम *के दौरान* स्वतंत्रता संग्राम अन्य बातों के साथ साथ अपनी भागीदारी के परिणामस्वरूप कैद किया गया था।इसके परिणामस्वरूप उनका सामान्य पारिवारिक जीवन टूट गया और कई मामलों में आर्थिक और वित्तीय सहित कई नुकसान हुए।दूसरी ओर, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि "अंदोलनकरियों" को भी इसी तरह का नुकसान हुआ था।हमें यह भी स्मरण चाहिए कि इसके विरुद्ध एक अधीनस्थ समुदाय द्वारा विरोध

औपनिवेशिक शासन विशेष रूप से लोकतंत्र में स्वतंत्र नागरिकों के विरोध से अलग है।इसके अलावा, हालांकि औपनिवेशिक शासन के से विरोध के लिए कैद करना नुकसान या पीड़ा का आकलन करने के लिए एक उचित पैमाना हो सकता है, लेकिन एक स्वतंत्र देश में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है।लोकतंत्र में एक लोकप्रिय उद्देश्य के लिए विरोध की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ होती हैं (जैसा कि उत्तराखंड आंदोलन में हुआ था), फिर भी सभी के परिणामस्वरूप कारावास नहीं हो सकता है।

85. श्री रमन कुमार शाह और श्री एस. एन. बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता, जो क्रमशः "अंडोलनकरियों" और राज्य के लिए हैं, ने तब भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 46 का उल्लेख विद्वान, जो भाग IV यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में हैं।उन्होंने इस आधार पर "आंदोलनकारियों" के लिए एक मामला बनाने अन्य बातों के साथ साथ कोशिश अन्य बातों के साथ साथ कि समाज के सभी "कमजोर वर्गों" के शैक्षिक और आर्थिक हित *को बढ़ावा* देना राज्य के लिए एक जनादेश है।फिर भी, वे इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं कि कैसे "आंदोलनकारियों" को समाज का एक कमजोर खंड कहा जा समर्थ है और उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्ति देने और फिर सरकारी सेवा में उनके लिए

आरक्षण देने का मतलब उनके शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना होगा, और यह उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 का जनादेश है।

86. श्री रमन कुमार शाह ने राजेंद्र पांडुरंग पगारे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2008 की रिट याचिका संख्या 5266) के **मामले में बॉम्बे, औरंगाबाद पीठ में उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है और तर्क दिया** है कि उक्त मामले में "परियोजना प्रभावित" व्यक्तियों के पक्ष में दिया गया आरक्षण वैध माना गया था।हालाँकि, चूंकि मेरा विचार है कि यद्यपि एक "आंदोलनकारी" की तुलना "परियोजना प्रभावित" व्यक्ति से नहीं जा सकती है, इसलिए उपरोक्त निर्णय से श्री रमन कुमार शाह को कोई मदद नहीं मिली है।

87. क्या "आंदोलनकारियों" को "कमजोर वर्ग" कहा जा सकता है जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता श्री एस. एन. बाबुलकर और श्री रमन कुमार शाह के मामले में है?कमजोर खंड क्या है, यह भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।फिर भी, यह एक व्यापक शब्द है, जिसमें न मात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े खंड शामिल होंगे, बल्कि हमारे समाज के कई अन्य खंड भी शामिल होंगे, जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, विस्थापित व्यक्ति, परियोजना प्रभावित व्यक्ति, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग आदि। यह फिर से सच है कि कोई विशेष खंड शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता है, फिर भी वह कमजोर खंड से संबंधित हो सकता है।दूसरे शब्दों में, "कमजोर खंड" समाज का एक ऐसा खंड है जो परिस्थितियों से कमजोर हो गया है और इसलिए, राज्य को ऐसे खंड के बचाव के लिए आगे आना चाहिए।

88. लेकिन किसी भी कल्पना के दायरे में "आंदोलनकारियों" को हमारे समाज से "कमजोर वर्ग" नहीं कहा जा सकता है।यह बहुत तार्किक रूप से और साथ ही तथ्यात्मक रूप से भी है।प्रासंगिक समय पर "आंदोलनकारियों" द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्यों से कुछ भी दूर किए बिना, जो एक कारण के लिए था, फिर भी 7 दिनों से कम कारावास किसी व्यक्ति को हमारे समाज के कमजोर वर्गों में नहीं गिना जा सकता है।दूसरा, हमारे सामने कोई अनुभवजन्य अध्ययन नहीं हुआ है, राज्य द्वारा कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है, जो यह दिखा सके कि उनके कारावास के कारण "अंदोलनकारियों" को जीवन और समाज में किसी भी प्रकार का नुकसान और बाधा का सामना करना पड़ा है, और इसके परिणामस्वरूप उन्हें समाज के एक कमजोर खंड के रूप में गिना जाना चाहिए।यदि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों को बारीखंड से देखें, तो हम पाएंगे कि यह प्रावधान मुख्य रूप से एक कमजोर वर्ग को "सामाजिक

अन्याय और सभी प्रकार के शोषण" से बचाने के लिए है।यह अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग और अन्य सभी सीमांत वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा की आवश्यकता है, न कि "आंदोलनकारी" से।यह कि "आंदोलनकारी" समाज का एक "कमजोर वर्ग" कभी नहीं बनाते हैं ।

श्री रमन कुमार शाह या विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमें हमारी संतुष्टि के लिए समझाया विद्वान था।इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 का सहारा लेना और इस तरह "आंदोलनकरियों" को एक कमजोर खंड का संरक्षण देना खारिज कर दिया जाता है।

89. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू आदेश के लिए, राज्य अपने नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।मुझे अपने मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहले (2004 के सरकारी आदेश संख्या 1269 दिनांक 11.08.2004 को ध्यान में रखते हुए) उनके बीच किसी आत्यन्तिक रूप प्रकार की प्रतिस्पर्धा आयोजित किए बिना सरकारी सेवा में "आंदोलनकारियों" को नियुक्ति देना स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन है।वास्तव में यह एक आरक्षण भी नहीं है, बल्कि अनावश्यक या दयालु नियुक्ति का एक रूप है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।नतीजतन, उक्त आदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिनांकित आदेश संख्या 1269 और अन्य सभी आदेशों निरस्त कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।इसी तरह, "उत्तराखंड राज्य आंदोलन के घायल/जेल गए *आंदोलन की* सेवा नियमावली, 2010" को असंवैधानिक और अधिकार अधिकारातीत कर दिया गया है।

90. सरकारी आदेश संख्या 1270 दिनांक 11.08.2004 द्वारा पहले

दिए गए क्षैतिज आरक्षण, जो बाद में "अंडोलनकरियों" के आश्रितों के परिवार के सदस्यों तक विस्तारित किए गए, बेहतर नहीं हैं।"अंदोलनकरियों" को आरक्षण देने के लिए राज्य द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भाग लिया था।बाकी लोगों से "आंदोलनकारियों" को सही ठहराने के लिए, यानी जिन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया, क्या एक "आंदोलनकारी" को कारावास का सामना करना पड़ा, जो कुछ मामलों में 24 घंटे से भी कम हो सकता है।मुझे लगता है कि "अन्डोलंकरी" का यह वर्गीकरण किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है जो "अन्डोलंकरी" को अन्डोलंकरी से अलग कर सकता है।

कई समूह से बाहर रह गए, और दूसरी बात यह है कि वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है।

91. यह सच है कि हमेशा एक तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि यह वर्गीकरण कम से कम कुछ ठोस मानदंडों के आधार पर किया जाना था ताकि एक "अंडोलंकरी" को बाकी से अलग किया जा सके, और इसलिए कारावास एक ऐसा मानदंड था जिसे अपनाया गया था।यह मानते हुए कि जिन्हें "अन्डोलंकरी" के रूप में परिभाषित किया गया था, जिन्हें अब "चिह्नित अन्डोलंकरी" कहा जाता है, वे एक अच्छी तरह से परिभाषित श्रेणी और वर्ग बनाते हैं, फिर भी प्रश्न यह होगा कि इन सभी का उद्देश्य क्या है।"आंदोलनकारी" के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण मात्र तभी उचित और वैध ठहराया जा सकता है जब राज्य न्यायालय को संतुष्ट करे कि एक "आंदोलनकारी" के साथ-साथ उसके आश्रितों (जैसा कि आरक्षण अब "आंदोलनकारी" के आश्रितों को भी दिया गया है) को किसी प्रकार की अक्षमता या नुकसान, एक प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा है, और इसलिए आरक्षण का उद्देश्य ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को बाकी के बराबर लाना था।क्या 6 दिन से कम समय के लिए पुलिस हिरासत में हिरासत को विकलांगता या बाधा कहा जा सकता है, ताकि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण को उचित ठहराया जा सके?ऐसा हो सकता था अगर कारावास स्वयं ऐसे व्यक्तियों को अग्रेतर नुकसान पहुँचाता।इस अदालत को सूचित किया गया है कि राज्य ने "अंदोलनकरियों" के विरुद्ध सभी मामलों को वापस ले लिया है और इसलिए, पुलिस हिरासत में 6 दिनों से कम समय के लिए हिरासत को स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किए गए कारावास के बराबर या उसी स्तर पर नहीं माना जा सकता है।इसी तरह, इसे रक्षा कर्मियों के आश्रितों द्वारा झेली गई अक्षमता के बराबर नहीं माना जा सकता है, जो कठिन इलाकों में अपने सेवा कार्य की प्रकृति से अपने परिवार को उसी

तरह की देखभाल और ध्यान देने में समर्थ नहीं हैं, जैसा कि एक नागरिक के लिए संभव है।इसलिए, मेरा मानना है कि "अंडोलनकरियों" का वर्गीकरण किसी भी उचित मानदंड पर आधारित नहीं है और इसका उन उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है जिन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए।

92. मुझे "अंदोलनकरियों" के लिए आरक्षण देने में कोई औचित्य, जनहित या सार्वजनिक उद्देश्य नहीं मिलता है।

जनसेवा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के से किया गया एक मनमाना वर्गीकरण समानता की अवधारणा की जड़ में कटौती करता है।डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में आगाह किया था कि राज्य को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने में सक्षम बनाते हुए राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिए न कि बेलगाम।उनके लगभग भविष्यसूचक शब्द, जिनका उल्लेख वर्तमान आदेश के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पहले ही किया जा चुका है, थे-"जब तक आप 'पिछड़े' के रूप में कुछ योग्यता वाले वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं, तब तक आरक्षण के पक्ष में किया गया अपवाद अंततः नियम को पूरी तरह से खा जाएगा।नियम का कुछ भी नहीं रहेगा।

93. थॉमस से ही वर्गीकरण की अवधारणा को बहुत महत्व दिया गया है और इस तरह के वर्गीकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।थॉमस में इसे इस प्रकार देखा गया थाः

> "54. आनुपातिक समानताक सिद्धान्त तभी लागू होता है जब समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए।यह हैरान करने वाला सवाल उठाएगाःकिसमें समान और असमान?इसलिए आनुपातिक समानता के सिद्धान्त में कुछ मानदंडों के लिए एक अपील शामिल है जिसके संदर्भ में अंतर उपचार उचित है।यदि ऐसा कोई महत्वपूर्ण सम्मान नहीं है जिसमें संबंधित व्यक्ति अलग-अलग हैं, तो भेदभावपूर्ण व्यवहार अनुचित होगा।लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के रूप में क्या अनुमति दी जानी चाहिए जैसे कि विभेदक उपचार को उचित ठहराएगा?"
>
> (जोर दिया गया)

94. इंद्र साहनी में दी गई ध्यान दें की टिप्पणी को भी यहाँ दोहराना आवश्यक होगा।इंद्र साहनी में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) आरक्षण प्रदान करने की शक्ति से पूर्ण नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के से अग्रेतर का वर्गीकरण किया जा सकता है।

भारत ने अत्यधिक वर्गीकरण और उसमें निहित घातक खतरों के बारे में आगाह किया थाः

> पीठ ने कहा, "मामले पर पूरी तरह से विचार करने पर, हमारी मत है कि खंड (4) आरक्षण की अवधारणा का संपूर्ण नहीं है, और इसे नहीं माना जा सकता है; यह केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का संपूर्ण है।मात्र इसलिए कि वर्गीकरण के एक रूप को एक विशिष्ट खंड के रूप में बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि खंड (1) में निहित वर्गीकरण की अवधारणा और शक्ति समाप्त हो जाती है।ऐसा कहना सिद्धान्त रूप में सही नहीं होगा।लेकिन इसके साथ ही एक बात स्पष्ट है।यह बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में है-अग्रेतर सभी अग्रेतर विभिन्न कारणों से नहीं-कि खंड (1) के से किसी भी प्रकार के अग्रेतर आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में, यदि आह्वान किया जाता है, तो राज्य को संतुष्ट करना होगा कि किसी विशिष्ट स्थिति के निवारण के लिए ऐसा प्रावधान करना (जनहित में) आवश्यक था।खंड (4) की उपस्थिति को विशेष उपचार के योग्य अग्रेतर अधिक वर्ग

बनाने की प्रवृत्ति पर एक बाधा के रूप में कार्य करना चाहिए।ऐसा कहने का कारण बहुत सरल है।यदि खंड (4) के साथ-साथ खंड (1) दोनों के से आरक्षण किया जाता है, तो मुक्त प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को तदनुसार समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसा करना उचित नहीं है।"

(महेत्व दिया गया)

95. एक अन्य स्थान पर, उसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अति वर्गीकरण के नुकसान के बारे में अपनी ध्यान दें रखा था ।

> "।.कल्याणकारी उपायों की दिशा में निर्देशित विधायी उपायों या कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में कभी भी विवाद नहीं हुआ है, लेकिन जब वे बाहरी मजबूरियों से घिर जाते हैं या मनमाने होते हैं, तो देश के उच्च न्यायालय "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं।(इंद्र साहनी, जैसा कि दातार द्वारा संदर्भित, पृष्ठ 272)।

96. इससे पहले राम कृष्ण डालमिया [10] में, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक उचित वर्गीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए कहा था कि जहां भी वर्गीकरण स्वयं तर्कहीन है और जहां स्पष्ट रूप से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है और जब ऐसे वर्गीकरणों को चुनौती दी जाती है, तो उन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए और यदि वे भेदभावपूर्ण हैं और कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए।

97. इस मामले का एक और पहलू है जिस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।एक बार विशेष श्रेणियों में पदों या नियुक्तियों पर आरक्षण तब भी बना रहता है जब शुरू में इस तरह के आरक्षण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई हो।स्वतंत्रता सेनानियों के बेटों और बेटियों के लिए शुरू में किए गए आरक्षण को उनके पोते-पोतियों तक बढ़ा दिया गया था और यह अभी भी जारी है।हाथ में मामले में, प्रारंभिक आरक्षण मात्र "अंदोलनकरियों" के लिए था जिसे बाद में "अंदोलनकरियों" की एक सीमित श्रेणी के परिवार के सदस्यों तक बढ़ा दिया गया, जैसे कि वे जो

या तो वर्ष’50 अधिक थे और या जो काम करने में अछम थे । यह आरक्षण दोबारा आंदोलनकारी के सदस्यों के लिए बढ़ गया ।

---

10. राम कृष्ण डालमिया बनाम एस. आर. तेंदुलकर, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538

50 वर्ष से अधिक आयु के या अक्षम थे।यह फिर से सभी "आंदोलनकारी" के परिवार के सदस्यों तक विस्तारित किया गया था।

98. किसी भी मामले में, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के उद्देश्यों के लिए "अंडोलनकरियों" का एक अलग वर्ग में वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 दोनों का उल्लंघन है।मुझे सरकारी सेवा में "आंदोलनकरियों" को आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं दिखता है।इस तरह का आरक्षण देने में उस समय की सरकार की राजनीतिक मजबूरियां कुछ ऐसी हैं जो हमारे जांच के दायरे से बाहर हैं, लेकिन मुझे यह अभिलेख चाहिए कि यह पूरी तरह से सत्ता का मनमाना प्रयोग था।सरकारी सेवा में आरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक अलग वर्ग के रूप में "अंदोलनकरियों" का वर्गीकरण किसी भी उद्देश्य या सामाजिक मानदंड को पूरा नहीं करता है।इसलिए, मैं सरकारी आदेश संख्या 1270/2004 दिनांकित 11.04.2008 और बाद के आदेश दिनांकित 08.11.2006,22.10.2008,13.12.2011 और अन्य सभी आदेशों को निरस्त करता हूं जिनके द्वारा इस तरह के आरक्षण या तो दिए गए हैं या समय-समय पर बढ़ाए गए हैं।

99. उपरोक्त मामले को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त सरकारी आदेशों और नियमों के अनुसरण में नियुक्तियां करने वाले सरकार के सभी परिणामी आदेश भी निरस्त कर दिए जाएंगे और अलग कर दिए जाएंगे।

100. फैसला देने से पहले, मुझे सभी वकीलों, श्री एस. एन. बाबूलकर, विद्वान महाधिवक्ता, श्री वी. बी. एस. नेगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एम. एस. पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता (न्याय मित्र), श्री परेश त्रिपाठी, मुख्य

स्थायी वकील, श्री एम. सी. पंत, श्री महेश चंद्र पंत, श्री सिद्धार्थ साह, श्री सी. के. शर्मा अधिवक्ताओं द्वारा किए विद्वान प्रयासों को अभिलेख पर रखना चाहिए।श्री रमन कुमार शाह का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। रमन कुमार शाह, जिन्होंने "अंदोलनकरियों" के लिए व्यक्तिगत रूप से तर्क दिया।श्री रमन कुमार शाह (जो इस अदालत में अधिवक्ता कर रहे हैं) ने इस मामले को स्वतंत्र रूप से उठाया है।हालाँकि मैं उनके तर्कों से सहमत नहीं हुआ, फिर भी उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं।

(सुधांशु धूलिया, जे.)

23.06.2017

अवनीत/-